



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 9—जून 15, 2013, शनिवार/ज्येष्ठ 19—ज्येष्ठ 25, 1935
No. 24] NEW DELHI, JUNE 9—JUNE 15, 2013, SATURDAY/JYAISTHA 19—JYAISTHA 25, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 मई, 2013

कम 1109 —केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय, 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:—

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क,
सेवाकर का कार्यालय,
हल्द्वानी, उत्तराखंड

[फ सं ई-11017/1/2012-हिन्दी-II]

चन्द्र भान नारनौली, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

New Delhi, the 29th May, 2013

S.O. 1109.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language, (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, whereof more than 80% of the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

Office of the Central Excise,
Customs and Service Tax,
Haldwani, Uttarakhand.

[F.No. E-11017/1/2012-Hindi-II]

CHANDER BHAN NARNAULI, Director (OL)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 2013

का.आ. 1110.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक, नामित करती है :—

सारणी

क्र.सं.	बैंक का नाम	मौजूदा निदेशक	नवीन व्यक्ति
	(1)	(2)	(3)
1.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	श्री बी. श्रीनिवास	श्री एस. गणेश, पीसीजीएम, भारतीय रिजर्व बैंक, बजटीय एवं व्यय नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मेन भवन, दूसरा तल, फोर्ट, मुम्बई-400 001
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	श्री चंदन सिन्हा	श्री दीपक सिंघल, पीसीजीएम एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
3.	पंजाब नैशलल बैंक	श्री एन. एस. विश्वनाथन	श्री बी. पी. कानूनगो, पीसीजीएम एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 13 एवं 15, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल
4.	सिंडिकेट बैंक	श्री ए. एस. राव	श्री एम. राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जोखिम निगरानी विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 22वां तल, फोर्ट, मुम्बई-400 001
5.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्री बी. पी. कानूनगो	श्री प्रदीप्ता के. जेना, मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पोस्ट बाक्स नं. 162, साउथ गांधी मैदान, पटना-800 001
6.	इंडियन बैंक	डॉ. एन. कृष्ण मोहन	श्री सथ्यान डेविड, मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्कल, टोंक रोड, पोस्ट बाक्स नं. 12, जयपुर

[फा. सं. 6/34/2013-बीओ-1]

श्रेया गुहा, निदेशक

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 31st May, 2013

S.O. 1110.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Directors of nationalized banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in column (2) of said Table, with immediate effect and until further orders :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Bank	Name of the Existing Director	Name of new persons
	(1)	(2)	(3)
1.	Oriental Bank of Commerce	Shri B. Srinivas	Shri S. Ganesh, PCGM, Reserve Bank of India, Department of Budgetary & Expenditure Control, Central Office, Main Building, 2nd Floor, Fort, Mumbai-400 001
2.	Union Bank of India	Shri Chandan Sinha	Shri Deepak Singhal, PCGM and Regional Director, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi-110 001
3.	Punjab National Bank	Shri N. S. Vishvanathan	Shri B. P. Kanungo, PCGM and Regional Director, Reserve Bank of India, 13 and 15, N. S. Road, Kolkata-700 001, West Bengal
4.	Syndicate Bank	Shri A. S. Rao	Shri M. Rajeshwar Rao, CGM, Reserve Bank of India, Risk Monitoring Department Central Office Building, 22nd Floor, Fort, Mumbai-400 001
5.	Punjab and Sind Bank	Shri B. P. Kanungo	Shri Pradipta K. Jena, CGM and Regional Director, Reserve Bank of India, P. B. No. 162, South Gandhi Maidan, Patna-800 001
6.	Indian Bank	Dr. N. Krishna Mohan	Shri Sathyan David, CGM and Regional Director, Reserve Bank of India, Rambagh Circle, Tonk Road, P. B. No. 12, Jaipur

[F. No. 6/34/2013-BO-I]

SREYA GUHA, Director

मानव संसाधन विकास मंत्रालय**(उच्चतर शिक्षा विभाग)****(राजभाषा यूनिट)**

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

कम 1111 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित क्षेत्रीय केन्द्रों को ऐसे कार्यालयों के रूप में जिसके 80 से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :

1. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, प्लॉट नं. जे-2/1, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 044
2. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, एफ 634-636, पालम एक्सटेंशन, रामफल चौक (नजदीक सेक्टर-7), द्वारका, नई दिल्ली-110 045
3. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, दूसरी मंजिल, बिस्कोमान टावर, पश्चिम गांधी मैदान, पटना-800 001, बिहार
4. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, सांची कॉम्प्लैक्स, तीसरा तल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन के सामने, शिवाजी नगर, भोपाल-462 018, मध्य प्रदेश
5. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, चौहान निवास बिल्डिंग, खलीनी, शिमला-171 002, हिमाचल प्रदेश
6. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, एस.सी.ओ.-208, सेक्टर-14, पंचकुला-134 109, हरियाणा
7. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली-110 002
8. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, सी-53, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201 305, उत्तर प्रदेश
9. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, बी-1/33, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024, उत्तर प्रदेश
10. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, रेस्ट हाऊस एंड ई. एम. ऑफिस हॉल, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर-492 007, छत्तीसगढ़
11. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, 70/79, सेक्टर-7, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302 020, राजस्थान
12. इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, 6, सुभाष मार्ग, सुभाष कॉलोनी, होमगार्ड कार्यालय के नजदीक, करनाल-132 001.

[सं 11011-1/2013-राभा]
आर पी सिंघेदिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****(O. L. UNIT)**

New Delhi, the 4th June, 2013

S.O. 1111.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Regional Centres of Indira Gandhi National Open University under the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) as offices, whose more than 80% members of the staff have acquired working knowledge of Hindi :

Sl. No.	Name and address of the Regional Centre
1.	IGNOU Regional Centre, Plot No. J-2/1, Block B-1, Mohan Cooperative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
2.	IGNOU Regional Centre, F-634-636, Palam Extn., Ramphal Chowk (Near Sector-7), Dwarka, New Delhi-110045
3.	IGNOU Regional Centre, IInd Floor, Biscoman Tower, West Gandhi Maidan, Patna-800 001, Bihar

Sl. No.	Name and address of the Regional Centre
4.	IGNOU Regional Centre, Sanchi Complex, IIIrd Floor, Opp. Board of Secondary Education, Shivaji Nagar, Bhopal-462 016, M.P.
5.	IGNOU Regional Centre, Chauhan Niwas Building, Khalini, Shimla-171 002, H.P.
6.	IGNOU Regional Centre, S.C.O.-208, Sector-14, Panchkula-134 109 (Haryana)
7.	IGNOU Regional Centre, Gandhi Samriti Evam Darshan Samiti, Rajghat, New Delhi-110 002
8.	IGNOU Regional Centre, C-53, Sector-62, Institutional Area, Noida-201 305, U.P.
9.	IGNOU Regional Centre, B-1/33, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226 024, U.P.
10.	IGNOU Regional Centre, Rest House & E.M. Office Hall, Sector-1, Shankar Nagar, Raipur-492 007, Chattisgarh
11.	IGNOU Regional Centre, 70/79, Sector-7, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302 020, Rajasthan
12.	IGNOU Regional Centre, 6, Subhash Marg, Subhash Colony, Near Home Gaurd Office, Karnal-132 001.

[F. No. 11011-1/2013-O.L. U.]

R. P. SISODIA, Jt. Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 2013

का.आ. 1112.—सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के अधिकारी श्री संजीत कुमार सेनापति को प्रबंधक (मानव संसाधन) के पद पर नियुक्त करती है, यह पद भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष है, तथा उक्त प्रयोजन के लिए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 नवम्बर, 2000 के एस.ओ. सं. 128 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, कॉलम 1 और 2 के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, क्रम सं. 4 के सामने, तालिका में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2
“4	श्री संजीत कुमार सेनापति को प्रबंधक (मानव संसाधन), एनटीपीसी लिमिटेड, तालचर थर्मल पावर स्टेशन
	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) इसके तालचर थर्मल पावर स्टेशन (ओडिशा) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबंधित सभी परिसर।

[फ सं 8/6/1992-थर्मल- I]

आई सी पी केसरी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत सरकार के दिनांक 16 नवम्बर, 2000 के एस.ओ. सं. 128 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 30 जून, 2004 के एस.ओ. सं. 1676 के माध्यम से पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 5th June, 2013

S.O. 1112.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Sanjit Kumar Senapati, Manager (Human Resources), an officer of the National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited) equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government of India and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O. 128, dated the 16th November, 2000, namely :—

2. In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entries under column 1 and 2, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2
“4 Shri Sanjit Kumar Senapati, Manager (Human Resources), NTPC Limited, Talcher Thermal Power Station.	All premises belonging to National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited) and under the Administrative Control of its Talcher Thermal Power Station (Odisha).

[F. No. 8/6/1992- TH-I]

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 128, dated the 16 November, 2000 and last amended *vide* number S.O. 1676, dated the 30th June, 2004.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

का.आ. 1113.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन संशोधन के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों/संशोधनों की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों/संशोधनों यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संशोधन संख्या-1 आईएस 638 : 1979 शीट के रबड़ जोड़ तथा रबड़ अन्तर्वेशित जोड़ की — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	कुछ नहीं	मार्च, 2013
2.	संशोधन संख्या-2 आईएस 9382 : 1979 टार एवं बिटुमनी सामग्रियों के परीक्षण की पद्धतियां थीन फिल्म ओवन परीक्षण द्वारा ताप एवं वायु के प्रभाव ज्ञात करना	कुछ नहीं	मई, 2013
3.	संशोधन संख्या-1 आईएस 4669 : 1968 पोलीविनाईल क्लोराइड रेजिन के लिए परीक्षण पद्धतियां	कुछ नहीं	मई, 2013
4.	संशोधन संख्या-1 आईएस 11720 भाग 1 : 1986 कृत्रिम रबड़ के परीक्षण की पद्धतियां भाग 1 एन्टीऑक्सीडेंट ज्ञात करना	कुछ नहीं	नवंबर, 2011
5.	संशोधन संख्या-1 आईएस 10171 : 1991 खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त प्लास्टिक हेतु मार्गदर्शिका (दूसरा पुनरीक्षण)	कुछ नहीं	मई, 2013

इन भारतीय मानकों/संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ पीसीडी/जी-7 (गजट)]

ए. के. दत्ता, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (पेट्रोलियम, कोयला एवं संबंधित उत्पाद)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 4th June, 2013

S. O. 1113.—In pursuance of Clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendments particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Year and Title of the Indian Standards/Amendments Established	No. and Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Amendment No. 1 to IS 638 : 1979 Specification for Sheet Rubber Jointing and Rubber Insertion Jointing (Second Revision)	NA	March, 2013
2.	Amendment No. 2 to IS 9382 : 1979 Methods for Testing Tar and Bituminous Materials : Determination of Effect of Heat and Air by Thin Film Oven Test	NA	May, 2013
3.	Amendment No. 1 to IS 4669 : 1968 Methods of Test for Polyvinyl Chloride Resins	NA	May, 2013
4.	Amendment No. 1 to IS 11720 (Part 1) : 1986 Methods of Test for Synthetic Rubber Part 1 Determination of Antioxidants	NA	November, 2011
5.	Amendment No. 1 to IS 10171 : 1999 Guide on Suitability of Plastics for Food Packaging (Second Revision)	NA	May, 2013

Copy of these Standards/Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref. PCD/G-7 (Gazette)]

A. K. DATTA, Scientist 'F' & Head (Petroleum, Coal and Related Products)

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

का.आ. 1114.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 12933 (भाग 2) : 2003 सौर सपाट पट्टिका संग्राहक-विशिष्ट भाग 2 घटक (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन नं. 3 मई 2013	तुरंत
2.	संशोधन नं. 1 आईएस 8451 : 2011 उच्च दाब के गैस सिलिण्डरों का आवधिक निरीक्षण एवं परीक्षण-रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन नं. 1 मई 2013	तुरंत
3.	संशोधन नं. 1 आईएस 15935 : 2011 मोटर वाहन के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) के ऑन-बोर्ड भंडारण हेतु समिश्र सिलिंडर-विशिष्ट	संशोधन नं. 1 जून 2013	तुरंत
4.	संशोधन नं. 3 आईएस 4379 : 2011 औद्योगिक गैस सिलिंडर में तत्व की पहचान (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन नं. 3 जून 2013	तुरंत

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ एम.ई.डी./जी-2 : 1]

तेजवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (यांत्रिक इंजीनियरिंग)

New Delhi, the 4th June, 2013

S. O. 1114.—In pursuance of Clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Year of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 12933 (PT 2) : 2003 Solar Flat Plate Collector-Specification : Part 2 Components (<i>Second Revision</i>)	Amendment No. 3 May 2013	With immediate effect

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Amendment No. 1 to IS 8451 : 2009 Periodic inspection and testing of high pressure gas cylinders-Code of Practice	Amendment No. 1 May 2013	With immediate effect
3.	Amendment No. 1 to IS 15935:2011 Composite cylinders for on-board storage of compressed natural gas (CNG) as a fuel for automotive vehicle—Specification	Amendment No.1 June 2013	-do-
4.	Amendment No. 3 to IS 4379:1981 Identification of the contents of industrial gas cylinders (<i>First Revision</i>)	Amendment No. 3 June 2013	-do-

Copies of this Amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram. On-line purchase of Indian Standard can be made at : <http://www.standardsbis.in>.

[Ref. MED/G-2 : 1]

T. V. SINGH, Scientist 'F' & Head (Mechanical Engineering)

नई दिल्ली, 5 जून, 2013

का.आ. 1115.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

अनुसूची

संशोधित भारतीय मानक(कों) की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)
आई एस 9537 (भाग 3) : 1983 की संशोधन संख्या 2	02 जून, 2011	31-05-2013

इस भारतीय संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी 14/टी-48]

आर. सी. मैथ्यू, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

New Delhi, the 5th June, 2013

S.O. 1115.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standard hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed has been issued :

SCHEDULE

No. and Year of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)
IS 9537 (Part 3) : 1983 Specification for conduits for electrical installations Part 3 Rigid plain conduits of insulating materials	02 June, 2011	31-05-2013

Copy of the Amendment is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref. ET 14/T-48]

R. C. MATHEW, Scientist 'F' and Head (Electrotechnical)

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

का.आ. 1116.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम 5 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं को लाइसेंस किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम. सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि वर्ष माह	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा संख्या	भाग	अनु	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	3944172	07 मई, 2013	मीराज इन्डस्ट्रीज 21, सम्राट इन्डस्ट्रीयल एरिया, एस टी वर्कशॉप के पीछे, गोंडल रोड, राजकोट, गुजरात-360004	एक फेजी छोटे एसी और यूनीवर्सल बिजली की मोटर	996	0	0	2009
02	3942875	01 मई, 2013	क्रिष्णा ज्वेलर्स कोर्ट रोड के पास, मानावडर, जूनागढ़, गुजरात-362630	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999
03	3944374	08 मई, 2013	श्री सौभाग्या कनकन 14, राज प्लाजा, पेलेस रोड, राजकोट, गुजरात-360001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999
04	3944475	08 मई, 2013	घनश्याम ज्वेलर्स जवेरी बाजार, भीमनाथ रोड, बावरा, जिला अमरेली, गुजरात-365421	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999
05	3946176	13 मई, 2013	श्री श्याम ज्वेलर्स हवेली मार्केट, काजीनो चकलो, मांडवी टॉवर, जामनगर, गुजरात-361001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999
06	3946277	13 मई, 2013	जोगीया ज्वेलर्स ग्राउन्ड फ्लोर, मानेक चौक, जवेरी बाजार, पोरबंदर, गुजरात-360575	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07	3948887	21 मई, 2013	कल्पद्रुम पहेली मंजिल, साटा बाजार, अलंकार चेम्बर, वेरावल जिला जूनागढ़, गुजरात-362265	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	1417	0	0	1999
08	3951169	29 मई, 2013	पाटन स्टील इन्डस्ट्रीज 305, तीसरी मंजिल, “सुरभी मोल”, बाधवाडी रोड, भावनगर, गुजरात-364240	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य विकसित इस्पात छड़ और तार	1786	0	0	2008
09	3947279	16 मई, 2013	अर्श अलोयस ऑफिस नं. 119, पहली मंजिल माधव दर्शन, बाधवाडी रोड, गुजरात-364001	सामान्य संरचना इस्पात हेतु पुनर्वेल्लन के लिये कार्बन ढलवा इस्पात इंगट, विलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्ट	2830	0	0	2012
10	3947380	16 मई, 2013	राज इस्पात ऑफिस नं. 119, पहली मंजिल, माधव दर्शन, बाधवाडी रोड, गुजरात-364001	सामान्य संरचना इस्पात हेतु पुनर्वेल्लन के लिये कार्बन ढलवा इस्पात इंगट, विलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्ट	2830	0	0	2012
11	3949283	21 मई, 2013	अजन इस्पात ऑफिस नं. 119, पहली मंजिल, माधव दर्शन, बाधवाडी रोड, गुजरात-364001	सामान्य संरचना इस्पात हेतु पुनर्वेल्लन के लिये कार्बन ढलवा इस्पात इंगट, विलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्ट	2830	0	0	2012
12	3951270	29 मई, 2013	जिनियस इलेक्ट्रोटेक लिमिटेड सर्वे नं. 43, मेधपर बोरीची, तहसील अंजार, गांधीनगर जिला कच्छ, गुजरात-370110	बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सर (द्रवीकारक और ग्राइंडर) की विशिष्ट	4250	0	0	1980
13	3948079	20 मई, 2013	रीलाइन्स पाइप इन्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 609, जीआईडीसी-2, जूनागढ़, गुजरात-362037	पानी की आपूर्ति के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलिएथिलीन पाइप- विशिष्ट	4984	0	0	1995
14	3948382	21 मई, 2013	श्री राम इन्डस्ट्रीज गोंडल रोड, सेन्ट मेरी स्कूल, जिला राजकोट, गोंडल, गुजरात-360311	पानी की आपूर्ति के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलिएथिलीन पाइप- विशिष्ट	4984	0	0	1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	3951371	29 मई, 2013	केपिटल पोलिप्लास्ट (गुजरात) प्रा. लि. सर्वे नं. 3 फ्लोर नं. 76-79 किशन दिहाइडेशन के पीछे, एन.एच. 27, तालुका गोंडल, भोजपुरा, जिला राजकोट, गुजरात-360311	पानी की आपूर्ति के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलिएथिलीन पाइप- विशिष्ट	4984	0	0	1995
16	3949788	24 मई, 2013	गुरुकृपा इलेक्ट्रिकल्स प्लॉट नं. 16, जलाराम इन्डस्ट्रीज एरिया, रुडा ट्रान्सपोर्ट नगर के पीछे, एनएच-8 बी, गुजरात-360003	निमज्जनीय पम्प सेट	8034	0	0	2002
17	3950672	28 मई, 2013	अंलकित मैन्युफेक्चरर्स “बासुकी एस्टेट” श्री हरी इन्डस्ट्रीयल एरिया, स्ट्रीट नं. 5, आजी रिंग रोड, गुजरात-360004	निमज्जनीय पम्प सेट	8034	0	0	2002
18	3951876	30 मई, 2013	लीवा पम्पस खोडियार होटल के पास, श्री हरी इन्डस्ट्रीज जोन-1, मैन रोड, आजी वसाहत रिंग रोड, राजकोट, गुजरात-360003	निमज्जनीय पम्प सेट	8034	0	0	2002
19	3952171	31 मई, 2013	एचएमपी पम्पस एसआर राजलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, एनएच 8-वी बावडी रोड, वावडी, जिला राजकोट, गुजरात-360004	निमज्जनीय पम्प सेट	8034	0	0	2002
20	3945275	31 मई, 2013	पेसीफिक इलेक्ट्रिकल्स प्लॉट नं. 10, सखिया नगर, गोकुलधाम मैन रोड, जिला राजकोट, गुजरात-360004	निमज्जनीय पम्प सेट की मोटरें	9283	0	0	1995
21	3944980	09 मई, 2013	डोल्फीन स्टोरेज सिस्टम प्रा.लि., प्लॉट नं. 1005-ए, फेज 3, जी.आई.डी.सी. वाधवान सिटी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात-363035	पानी के भण्डार हेतु टैंकियां	12701	0	0	1996

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	3949182	23 मई, 2013	गुरुकृपा इलेक्ट्रीकल्स प्लॉट नं. 16, जलाराम इन्डस्ट्रीज ऐरीया, गुडा ट्रांसपोर्ट नगर, एनएच-8वी, राजकोट, गुजरात-360003	खुले कुएं के लिए निमज्जय पम्प सेट	14220	0	0	1994

[सं. केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:11]

एम. राधाकृष्णा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 6th June, 2013

S.O. 1116.—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certificate) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	3944172	07-05-2013	M/s Miraj Industries 21, Samrat Industrial Area, Behind S.T. Work Shop, Gondal Road, Rajkot, Gujarat-360004	Single-phase small ac and universal electric motors	996	0	0	2009
02.	3942875	01-05-2013	M/s Krishna Jewellers Near Court Road, Manavadar, Junagadh, Gujarat-362630	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999
03.	3944374	08-05-2013	M/s Shri Saubhagya Kankan 14, Raj Plaza, Palace Road, Rajkot Gujarat-360001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999
04.	3944375	08-05-2013	M/s Ghanshyam Jewellers Zaveri Bazar, Bhimnath Road, Babra, District : Amreli, Gujarat-365421	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999
05.	3946176	13-05-2013	M/s Shree Shyam Jewellers Haveli Market, Kaji No Chaklo, Mandavi Tower, Jamnagar, Gujarat-361001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06.	3946277	13-05-2013	M/s Jogia Jewellers Ground Floor, Manek Chowk, Zaveri Bazar, Porbandar, Gujarat-360575	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999
07.	3948887	21-05-2013	M/s Kalpdrum First Floor, Satta Bazar, Alankar Chamber, Veraval, Distt. Junagadh Gujarat-362265	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking- Specification	1417	0	0	1999
08.	3951169	29-05-2013	M/s Patran Steel Industries Patran Steel Industries 305, 3rd Floor, “Surbhi Mall” Waghwadi Road, Bhavnagar, Gujarat-364240	Specification for high strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement	1786	0	0	2008
09.	3947279	16-05-2013	M/s Arsh Alloys Office No. 119, At 1st Floor, Madhav Darshan, Waghawadi Road, Bhavnagar, Gujarat-364001	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	2830	0	0	2012
10.	3947380	16-05-2013	M/s Raj Ispat Office No. 119, Madhav Darshan, 1st Floor, Waghawadi Road, Bhavnagar, Gujarat-364001	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	2830	0	0	2012
11.	3949283	21-05-2013	M/s Azan Ispat Street No. 2, Madhiya Road, Kumbharwada, Bhavnagar, Gujarat-364006	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	2830	0	0	2012
12.	3951270	29-05-2013	M/s Genus Electrotech Limited Survey No. 43, Meghpar Borichi, Taluka-Anjar, Gandhidham, District : Kachchh Gujarat-370110	Specification for Domestic Electric Food- Mixers (Liquidizes and Grinders)	4250	0	0	1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	3948079	20-05-2013	M/s Reliance Pipe Industries Plot No. 609, GIDC-2, Junagadh, Gujarat-362037	Specification for high density polyethylene pipes for potable water supplies	4984	0	0	1995
14.	3948382	21-05-2013	M/s Shree Ram Industries Gondal Road, Near Saint Marry School, District Rajkot, Gondal, Gujarat-360311	Specification for high density polyethylene pipes for potable water supplies	4984	0	0	1995
15.	3951371	29-05-2013	M/s Capital Polyplast (GUJ.) PVT. Ltd. Survey No. 3, Plot No. 76-79, Behind Kisan Dehydration NH-27, Taluka Gondal, Bhojpara District : Rajkot Gujarat-360311	Specification for high density polyethylene pipes for potable water supplies	4984	0	0	1995
16.	3949788	24-05-2013	M/s Gurukrupa Electricals Plot No. 16, Jalaram Ind. Area, Behind RUDA Transport Nagar, NH-8B, Gujarat-360003	Submersible Pumpsets Specification	8034	0	0	2002
17.	3950672	28-05-2013	M/s Alankit Manufacturers “Vasuki Estate”, Shri Hari Industrial Area, Street No. 5, Aji Ring Road, Gujarat-360004	Submersible Pumpsets Specification	8034	0	0	2002
18.	3951876	30-05-2013	M/s Leeva Pumps Near Shri Khodiyar Hotel, Shri Hari Ind. Zone-1, Main Road, Aji Vasahat Ring Road, Rajkot, Gujarat-360003	Submersible Pumpsets Specification	8034	0	0	2002
19.	3952171	31-05-2013	M/s HMP Pumps C/o-SR Rajlakshmi Ind., Shivam Ind. Estate N.H. 8-B, Vavdi Road, Vavdi, District Rajkot, Gujarat-360004	Submersible Pumpsets Specification	8034	0	0	2002
20.	3945275	10-05-2013	M/s Pacific Electricals Plot No. 10, Sakhiya Nagar Gokuldharm Main Road, District : Rajkot, Gujarat-360004 Rajkot, Gujarat-360003	Motors for Submersible Pumpsets-Specification	9283	0	0	1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21.	3944980	09-05-2013	M/s Dolphin Storage Systems Pvt. Ltd., Plot No. 1005-A, Phase III G.I.D.C., Wadhwan City. District: Surendernagar Gujarat-363035	Specification for rotational moulded polyethylene water storage tanks	12701	0	0	1996
22.	3949182	23-05-2013	M/s Gurukrupa Electricals Plot No. 16, Jalaram Ind. Area, Behind Ruda Transport-nagar Gujarat-360003	Openwell Submersible Pumpsets-Specification	14220	0	0	1994

[No. CMD/13:11]

M. RADHAKRISHNA, Scientist 'F' and Head

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

का.आ. 1117.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, के लाइसेंस रद्द किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम	रद्दीकरण तिथि
1.	7949711	अलमाईटी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जी 1934-35, लोधीका जीआईडीसी, मेटोडा, तालुका लोधीका, जिला राजकोट, गुजरात-360021	हस्तप्रचलित उर्वरक ब्राडकास्टर्स की विशिष्टि	17 मई, 2013

[सं. केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:11]

एम. राधाकृष्णा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 6th June, 2013

S. O. 1117.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certificate) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below have cancelled/suspended with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards Covered by the licence cancelled/suspension	Date of Expiry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7949711	M/s. Almighty Agrotech Pvt. Ltd., G-1934-35, Lodhika GIDC, Metoda, Talula Lodhika District : Rajkot, Gujarat-360021	Specification for Manually Operated Fertilizer Broadcaster	17-5-2013

[No. CMD/13:11]

M. RADHAKRISHNA, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

का.आ. 1118.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है उसे वापिस ले लिया गया है :

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किये गये भारतीय मानक की संख्या, वर्ष और शीर्षक	भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) में का. आ. संख्या और तिथि प्रकाशित	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 1448 (भाग 45) : 1962 विमानन पद्धति द्वारा विमानन ईंधन का अपस्फोट अभिलक्षण	—	मानक अप्रचालित हो गया है

[संदर्भ पीसीडी/जी-7 (गजट)]

ए. दत्ता, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (पीसीडी)

New Delhi, the 6th June, 2013

S.O. 1118.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, it is, hereby notified that the Indian Standard, particulars of which are mentioned in the Schedule hereinafter has been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Cancelled	S.O. No. & Date published in the Gazette India, Part II, Section 3, Sub-section (ii)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1448 (Part 45): 1962 Knock Characteristics of Aviation Fuels by the Aviation Method	—	The Standard has become obsolete

[Ref. PCD/G-7 (Gazette)]

A. DATTA, Scientist 'F' & Head (PCD)

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1119.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 1879:2010 धातवर्धक ढलवां लोहा पाइप फिटिंग-विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3 मार्च 2013	04-06-2013

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ एमटीडी 6/T-1]

पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 7th June, 2013

S.O. 1119.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment, Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	IS. No. & Title of the amendment (s)	No. & year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS1879:2010 Malleable cast iron pipe fittings—Specification (<i>third revision</i>)	Amendment No. 3 March 2013	04-06-2013

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of India Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkatta Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD 6/T-1]

P. GHOSH, Scientist 'F' & Head (Met Engg.)

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1120.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों का संशोधन का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन संख्या और वर्ष	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 13690 : 1992 पाश्चुरिकृत मक्खन-विशिष्ट	संशोधन संख्या 1 वर्ष 2013	31 मार्च, 2013

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ एफएडी/जी-128]

कुमार अनिल, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (खाद्य एवं कृषि)

New Delhi, the 7th June, 2013

S.O. 1120.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment, Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian standards	No. & year of the Amendment	Date of which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 13690 : 1992 Pasteurized Butter-Specification	Amendment No. 1 Year 2013	31 March, 2013

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of India Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi.

[Ref. FAD/G-128]

KUMAR ANIL, Scientist 'F' and Head (Food and Agriculture)

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1121.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 629:2013 साईकिल-हब असेम्बलि-विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)	आई एस 12205:1988 का समामेलन	फरवरी 2013
2.	आई एस 4692:2013 पोतनिर्माण विद्युत वेल्डिड स्टड रहित एंकर जंजीरें तथा संयोजी सांकलें-विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	—	मार्च 2013

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ टी ई डी/जी-16]

पी. सी. जोशी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (टी ई डी)

New Delhi, the 7th June, 2013

S.O. 1121.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard, particulars of which are mentioned in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & title of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 629:2013 Bicycle-Hub assembly Specification (Second Revision)	Amalgamating IS 12205:1988	February 2013
2.	IS 4692:2013 Shipbuilding—Electrically welded studless link anchor chains and connecting shackles—Specification (Second Revision)	—	March 2013

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of India Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. TED/G-16]

P. C. JOSHI, Scientist 'F' & Head (Transport Engg.)

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1122.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किये गये मानक की संख्या और वर्ष	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में का.आ. संख्या और तिथि प्रकाशित	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 7915:1976 एयरक्राफ्ट ग्राउंड इलैक्ट्रिकल सप्लाय के संयोजनों की विमाएँ	—	आई एस/आई एस ओ 13835 (भाग 2):2012 के द्वारा अतिक्रमण
2.	आई एस 8422 (भाग 9) : 1986 आई सी इंजनों के पिस्टन रिंगों की विशिष्टि : भाग 9 शब्दावली एवं परिभाषाएँ	—	आई एस/आई एस ओ 6621-1:2007 के द्वारा अतिक्रमण

[संदर्भ टी ई डी/जी-16]

पी. सी. जोशी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (टी ई डी)

New Delhi, the 7th June, 2013

S.O. 1122.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it is, hereby notified that the Indian Standards, Particulars of which are mentioned in the Schedule give hereafter, have been cancelled and stand withdrawn.

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Cancelled	S.O. No. & Date published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section(ii)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 7915:1976 Dimensions for connections for aircraft ground electrical supplies	—	Superseded by IS/ISO 13835(Part 2):2012
2.	IS 8422(Part 9): 1986 Specification for piston rings for IC Engines: Part 9 Terms and definitions	—	Superseded by IS/ISO 6621-1:2007

[Ref. TED/G-16]

P. C. JOSHI, Scientist 'F' & Head (Transport Engg.)

नई दिल्ली, 10 जून, 2013

का.आ. 1123.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 12235 (भाग 4): 2004	संशोधन संख्या 1 जून, 2013	30 जून, 2013

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ सीईडी/राजपत्र]

सी. आर. राजेन्द्रा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 10th June, 2013

S.O. 1123.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 12235 (Part 4): 2004	Amendment No. 1, June 2013	30-06-2013

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of India Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. CED/Gazette]

C. R. RAJENDRA, Scientist 'F' and Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 10 जून, 2013

का.आ. 1124.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 15778:2007	संशोधन संख्या 2, मई, 2013	17 मई, 2013

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ सीईडी/राजपत्र]

सी. आर. राजेन्द्रा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 10th June, 2013

S.O. 1124.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 15778:2007	Amendment No. 2, May 2013	17-05-2013

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of India Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. CED/Gazette]

C. R. RAJENDRA, Scientist 'F' and Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 12 जून, 2013

का.आ. 1125.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :

अनुसूची

भारतीय मानक संख्या	भाग	अनु.	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर		इकाई दर स्लैब (रु.)	स्लैब में इकाईयां	शेष	प्रचालन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1319	-	-	1983	खाद्य टेपियोका स्टार्च	एक टन	रु. 34000	रु. 29000	रु. 24	सभी	-	12-2-2013
3899	-	-	1981	जिनेब घुलनशील पाउडर	एक टन	रु. 34000	रु. 29000	रु. 24	सभी	-	12-2-2013
5346	-	-	1994	संश्लिष्ट खाद्य रंग निमित्तियां और मिश्रण (पाउडर के लिए)	एक किग्रा.	रु. 34000	रु. 29000	रु. 0.26	सभी	-	12-2-2013
5346	-	-	1994	संश्लिष्ट खाद्य रंग निमित्तियां और मिश्रण (लिक्विड के लिए)	एक लिटर	रु. 34000	रु. 29000	रु. 0.45	सभी	-	12-2-2013
7180	-	-	1973	डिस्पोजेबल आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन ग्लब्स	1000 नग	रु. 39000	रु. 34000	रु. 1.50	सभी	-	12-2-2013
15298	4	-	2010	निजी सुरक्षा उपस्कर भाग 4 व्यवसाय में पहनने वाले फुटवियर	एक जोड़ा	रु. 72000	रु. 61000	रु. 1.40	सभी	-	12-2-2013

[सं. सीएमडी/13:10]

पी. के. गम्भीर, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रधान (प्रमाणन)

New Delhi, the 12th June, 2013

S.O. 1125.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the products given in the schedule :

IS No.	Part	Sec.	Year	Product	Unit	Minimum Marking Fee Large Scale Small Scale		Unit Rate Slab-1	Unit in Slab-1	Remai-ning	Effective Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1319	-	-	1983	Edible Tapioca Starch	One Tonne	Rs. 34000	Rs. 29000	Rs. 24	All	-	12-2-2013
3899	-	-	1981	Zinab Water Dispersible Powder	One Time	Rs. 34000	Rs. 29000	Rs. 24	All	-	12-2-2013
5346	-	-	1994	Synthetic Food Colour Preparation and Mixtures	One Kg. (for Powder)	Rs. 34000	Rs. 29000	Rs. 0.26	All	-	12-2-2013
5346	-	-	1994	Synthetic Food Colour-Preparation and Mixtures	One litre (for Liquid)	Rs. 34000	Rs. 29000	Rs. 0.45	All	-	12-2-2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7180	-	-	1973	Disposable Artificial Insemination Gloves	1000 Pieces	Rs. 39000	Rs. 34000	Rs. 1.50	All	-	12-2-2013
15298	4	-	2010	Personal Protective Equipment Part 4, Occupational Footwear	One Pair	Rs. 72000	Rs. 61000	Rs. 1.40	All	-	12-2-2013

[No. CMD/13:10]

P. K. GAMBHIR, Scientist 'G' & Chief (Certification)

कृषि मंत्रालय**(कृषि और सहकारिता विभाग)**

नई दिल्ली, 10 जून, 2013

का.आ. 1126.—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में मद (ix), (x), (xi) (xii), और मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “(ix) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कृषक संगठन से एक प्रतिनिधि श्री पी. चेंगल रेड्डी, भारत कृषक सहयोजन परिसंघ, हैदराबाद –सदस्य;
- (x) जनजातीय संगठन के एक प्रतिनिधि—श्री मायाराम नेताम, सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी और दूरदर्शन मार्फत वृंदावन कालोनी, मकान नं. 1/21 जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ –सदस्य;
- (xi) बीज उद्योग से एक प्रतिनिधि—डा. ऊषा बरवाले, महाराष्ट्र संकर बीज कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र –सदस्य;
- (xii) कृषि विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि—डा. बी. एस. दिल्ली, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय –सदस्य;
- (xiv) राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधि—(i) प्रधान सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार (ii) प्रधान सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश सरकार –सदस्य” ।

3. पूर्वोक्त सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

[फा. सं. 2-3/2009-एस.डी. V]

राम कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 11 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन सं. का.आ. 1883(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2006, सं. का.आ. 1316(अ), तारीख 11 मई, 2009, सं. का.आ. 3064(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2009, सं. का.आ. 195(अ), तारीख 31 जनवरी, 2011 और सं. का.आ. 1726(अ), तारीख 31 जुलाई, 2012 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Co-operation)**

New Delhi, the 10th June, 2013

S.O. 1126.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, “Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O.1589 (E), dated the 11th November, 2005, namely :—

2. In the said notification, for items, (ix), (x), (xi), (xii) and (xiv) and the entries relating thereto, following items and entries shall be substituted, namely :—

- “(ix) One representative from a National or State level Farmers’ organization- Shri. P. Chengal Reddy, Federation of Farmers Association India, Hyderabad —Member;
- (x) One representative from a Tribal Organisation- Shri. Mayaram Nettam, Retired Program Officer, AIR and Doordarshan C/o Vrindavan Colony, House No. 1/21, Jagadapur, Bastar, Chattisgarh —Member;
- (xi) One representative from Seed Industry: Dr. Usha Barwale, Maharashtra Hybrid Seeds Company Limited, Maharashtra —Member;
- (xii) One representative from Agricultural University- Dr. B. S. Dhillon, Vice Chancellor, Punjab Agriculture University —Member;
- (xiv) Two representatives of State Governments- (i) Principal Secretary (Agriculture), Government of Maharashtra. (ii) Principal Secretary (Agriculture), Government of Uttar Pradesh —Members”.

3. The terms of office of the aforesaid Member shall be for a period of three years from the date of their appointment.

[F. No. 2-3/2009-SD. V]

RAM KUMAR, Under Secy.

Note : —The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 11th November, 2005, *vide* No. S.O. 1589 (E), dated the 11th November, 2005 and subsequently amended *vide* No. S.O. 1883 (E), dated the 1st November, 2006, No. S.O. 1316 (E), dated the 11th May, 2009, No. S.O. 3064 (E), dated the 30th November, 2009, No. S.O. 195 (E), the 31st January, 2011 and No. S.O. 1726 (E), dated the 31st July, 2012.

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जून, 2013

का.आ. 1127.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 की 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 456(अ), तारीख 22 फरवरी, 2013 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 25 फरवरी, 2013 में प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) [210.20 हेक्टर

(लगभग) या 519.19 एकड़ (लगभग) में सभी अधिकार और 19.00 हेक्टर (लगभग) या 46.93 एकड़ (लगभग) में खनन अधिकार] में उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने कि लिए अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकतोडिया, डाकघर दिशरगढ़, जिला बर्दवान-713333, पश्चिम बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि [210.20 हेक्टर (लगभग) या 519.19 एकड़ (लगभग) में सभी अधिकार और 19.00 हेक्टर (लगभग) या 46.93 एकड़ (लगभग) में खनन अधिकार] में के पूर्वोक्त अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 25 फरवरी, 2013 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित होंगे, अर्थात् :-

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिसूचना की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के पूर्वोक्त अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा तथा उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- (4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और भूमि में या उसके ऊपर इस प्रकार निहित अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं, पालन करेगी।

[फा. सं. 43015/28/2009-पीआरआईडब्ल्यू-1]

वी. एस. राणा, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 11th June, 2013

S.O. 1127.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 456(E), dated the 22nd February, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 25th February, 2013, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land [all rights in 210.20 hectares (approximately) or 519.19 acres (approximately) and mining rights in 19.00 hectares (approximately) or 46.93 acres (approximately)] described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances, under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, At-Sanctoria, Post Office Disergarh, District Burdwan-713333, West Bengal (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs, that the said land [all rights in 210.20 hectares (approximately) or 519.19 acres (approximately) and mining rights in 19.00 hectares (approximately) or 46.93 acres (approximately)] so vested

shall, with effect from the 25th February, 2013, instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (1) the Government company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the said Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (3) the Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said land so vested;
- (4) the Government company shall have no power to transfer the said land and the rights in or over the said land so vested, to any other person without the prior approval of the Central Government; and
- (5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/28/2009-PRIW-I]

V. S. RANA, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

का.आ. 1128.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना, ए-13, सेक्टर 1, अवन्ति विहार, रायपुर -492006 (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा;

अनुसूची

तहसील : पिथौरा

जिला : महासमुंद

राज्य : छत्तीसगढ़

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	रेमडा	16/1084	00	06	84
2.	तिलंजनपुर	311/3	00	14	47
3.	सावित्रीपुर	309/884	00	18	87
4.	अठारागुडी	454	00	02	40
5.	सरकडा	612	00	06	15

[फा. सं. आर-25011/21/2010-ओ.आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th June, 2013

S.O. 1128.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), a “Pipeline” should be laid in State of Chhattisgarh by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip – Sambalpur – Raipur – Ranchi Pipeline Project, A-13, Sector -1, Avanti Vihar, Raipur -492006, Chhattisgarh.

SCHEDULE

Tehsil : Pithora

District : Mahasamund

State : Chhattisgarh

Sl. No	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	Remda	16/1084	00	06	84
2.	Tilanjapur	311/3	00	14	47
3.	Sawitripur	309/884	00	18	87
4.	Atharagudi	454	00	02	40
5.	Sankara	612	00	06	15

[F.No. R-25011/21/2010-OR-1]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

का.आ. 1129.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना, ए-13, सेक्टर 1, अवन्ति विहार, रायपुर -492006 (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : सरायपाली

जिला : महासमुंद

राज्य : छत्तीसगढ़

क्रम. सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मोखापुटका	2098	00	13	60

[फा. सं. आर-25011/20/2010-ओ आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 2013

S.O. 1129.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), a “Pipeline” should be laid in State of Chhattisgarh by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip – Sambalpur – Raipur – Ranchi Pipeline Project, A-13, Sector -1, Avanti Vihar, Raipur -492006, Chhattisgarh.

SCHEDULE

Tehsil : Saraipali

District : Mahasamund

State : Chhattisgarh

Sl. No	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Mokhaputka	2098	00	13	60

[F. No. R-25011/20/2010-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2013

का.आ. 1130.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना, ए-13, सेक्टर 1, अर्वाटि विहार, रायपुर -492006 (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : बसना		जिला : महासमुंद	राज्य : छत्तीसगढ़		
क्रम. सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मेढ़ापाली	213	00	34	68
		464	00	06	66
2	पिलवापाली	589	00	01	07
3	खोगसा	715/2	00	09	57
4	घुटीकोना	564/5	00	03	48
5	भर्वरचुवा (टु.)	46/3	00	04	13
6	बुन्देलाभांठा	536	00	02	73
7	गौरटेक	613/2	00	08	30
		1712	00	00	91
		1652	00	09	20
8	हबेकांटा	498/3	00	00	60
9	खटखटी	1	00	07	40

[फा. सं. आर-25011/19/2010-ओ आर-1]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 2013

S.O. 1130.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), a “Pipeline” should be laid in State of Chhattisgarh by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip – Sambalpur – Raipur – Ranchi Pipeline Project, A-13, Sector -1, Avanti Vihar, Raipur -492006, Chhattisgarh.

SCHEDULE

Tehsil : Basna

District : Mahasamund

State : Chhattisgarh

Sl. No	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Medhapali	213	00	34	68
		464	00	06	66
2	Pilwapali	589	00	01	07
3	Khogsa	715/2	00	09	57
4	Ghutikona	564/5	00	03	48
5	Bhawarchuwa(Part)	46/3	00	04	13
6	Bundelabhantha	536	00	02	73
7	Gaurtak	613/2	00	08	30
		1712	00	00	91
		1652	00	09	20
8	Hawekanta	498/3	00	00	60
9	Khatkhati	1	00	07	40

[F. No. R-25011/19/2010-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1131.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी पाइपलाईनों के लिये सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये श्री एम. आर. वासुदेवन, डिप्टी कलेक्टर, तमिलनाडु सरकार, को दिनांक 4-5-2013 से प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एल-14014/10/13-जी.पी.]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2013

S.O. 1131.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorized Shri M.R. Vasudevan, Deputy Collector, Government of Tamilnadu to perform the functions of Competent Authority for all pipelines of GAIL (India) Limited, under the said Act, within the territory of Tamilnadu State & Union Territory of Puducherry w.e.f. 4-5-2013.

[F. No. L-14014/10/13-GP.]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 2013

का.आ. 1132.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12 के उप-नियम (2) के साथ पठित, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्सपेक्टोरेट ग्रिफ्थ इंडिया प्राइवेट लि. 14/253(8), दूसरा तल, पेरियरा चेम्बर्स, पी जोस वाज रोड, सीटी एरिया, वास्को-दा-गामा, गोवा- 403 802 भारत में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3975 तारीख 20 दिसम्बर, 1965 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों और अयस्कों समूह - I अर्थात् लौह अयस्क का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त खनिजों और अयस्कों का गोवा में, निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक अधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् :—

- (i) मैसर्स इन्सपेक्टोरेट ग्रिफ्थ इंडिया प्राइवेट लि. 14/253(8), दूसरा तल, पेरियरा चेम्बर्स, पी जोस वाज रोड, सीटी एरिया, वास्को-दा-गामा, गोवा 403 802 खनिज और अयस्क, समूह-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण करने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई निरीक्षण की पद्धति की जांच करने के लिए इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी;
- (ii) मैसर्स इन्सपेक्टोरेट ग्रिफ्थ इंडिया प्राइवेट लि. 14/253(8), दूसरा तल, पेरियरा चेम्बर्स, पी जोस वाज रोड, सीटी एरिया, वास्को-दा-गामा, गोवा-403 802 इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में निदेशक (खनिज और क्वालिटी नियंत्रण) द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए निदेशों से आबद्ध होंगे ।

[फा. सं. 4/1/2013-निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 5th June, 2013

S.O. 1132.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Inspectorate Griffith India Pvt. Ltd., 14/253(8), 2nd Floor, Pereira Chambers, Pe Jose Vaz Road, City Area, Vasco-da-Gama, Goa- 403 802, India as an Agency for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals and Ores Group-I, namely, Iron Ore, specified in the Schedule annexed to the Ministry of Commerce notification number S.O. 3975, dated the 20th December 1965, prior to export of said minerals and ores at Goa, subject to the following conditions, namely: —

- (i) M/s Inspectorate Griffith India Pvt. Ltd., 14/253(8), 2nd Floor, Pereira Chambers, Pe Jose Vaz Road, City Area, Vasco-da-Gama, Goa- 403 802, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in carrying out the inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965; and
- (ii) M/s Inspectorate Griffith India Pvt. Ltd., 14/253(8), 2nd Floor, Pereira Chambers, Pe Jose Vaz Road, City Area, Vasco-da-Gama, Goa- 403 802, in the performance of its function under this notification shall be bound by such directions as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing, from time to time.

[F. No. 4/1/13-Export Inspection]

A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 2013

कम 1133 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी पी डब्ल्यू डी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 7/2008) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22.05.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-42012/191/2005-आईआर(सीएम- II)]

बी एम पटनायक, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd May, 2013

S.O. 1133.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 7/2008) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Electrical Division-12, CPWD, and their workmen, received by the Central Government on 22.05.2013.

[No. L-42012/191/2005-IR (CM-II)]

B. M. PATNAIK, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE DR. R.K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, KARKARDOOMA
COURTS COMPLEX, DELHI.**

I.D. No. 7/2008

The General Secretary,
All India CPWD (MRM)
Karamchari Sangathan,
4823, Balbir Nagar Extension,
Gali No. 13, Shahadara,
Delhi-110032.

.....Workman

Versus

The Executive Engineer (E),
Electrical Division-12, CPWD,
Kitab Mahal, B.K.S. Marg,
New Delhi-110001

....Management

AWARD

Arbitration Award for re-categorization and reclassification of workmen in Central Public Works Department (in short the management) was passed in the year 1988. It was implemented with effect from 01.01.1973 (notionally) and financial benefits were accorded with effect from 01.04.1981. On implementation of the Arbitration Award, post of Assistant Operator was merged with operator and they were entitled for grant of selection grade on completion of eight years of regular service.

2. Shri Dwarka Prasad, who was working as operator with the management, had superannuated on November 1993. He was not given wages of highly skilled artisan, viz. Operator, by the management. As such, he got less gratuity and pensionary benefits. His claim for leave encashment was also declined. Aggrieved by that act of the management, he raised an industrial dispute. Since his claim was contested by the management, conciliation proceedings ended into a failure. On consideration of the failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. 2, New Delhi, vide order No. L/42012/191/2005-IR(CM-II), New Delhi dated 24.03.2008 with following terms:

"Whether the demand of all India CPWD (MRM) Kramchari Sangathan for revision of pension, gratuity and leave encashment of Shri Dwarka Prasad is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled to?

3. Claim statement was filed by Shri Dwarka Prasad, wherein he pleaded that on implementation of Arbitration Award, he was to be re-classified as highly skilled artisan and placed in scale of pay of Rs. 330-560 with effect from 01.03.1973 and Rs. 1200-2040 with effect from 01.01.1986, on completion of eight years of regular service. Management, failed to grant him pay in the aforesaid two scales of pay. He superannuated on 30.11.1993. According to him, an amount of Rs. 1,15,042.00 is due as arrears from the management, besides revision of his pension.

4. Management demurred his claim projecting that vide its order dated 25.09.1998 in CWP No. 87/97 and 106/97, High Court of Delhi announced that after merger of various categories in terms of Arbitration Award, if a workman is to be upgraded to the next higher category in that stream, it would be an element of promotion and the workman had to undergo trade test, if so prescribed. It has been disputed that Shri Dwarka Prasad was reclassified highly skilled artisan from 01.01.1973 notionally and with effect from 01.04.1981 with financial benefits. Shri Dwarka Prasad was not entitled for automatic upgradation without qualifying the trade test. He never qualified trade test, hence was not entitled to receive wages in scale of Rs. 330-560 and Rs. 1200-2040 with effect from 01.01.1986. His claims for receipt of arrears of Rs. 115042 and revision of pension are not maintainable. Management projects that the claim, being devoid of merits, is liable to be dismissed.

5. Vide notification No. A-11016/3/2009-CLS-II, New Delhi dated 03.04.2013, additional charge of the post of the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, was assigned to the undersigned by the appropriate Government and thus, this case reached this Tribunal for adjudication.

6. During the course of adjudication, Shri Satish Kumar Sharma, General Secretary of CPWD (MRM) Karamchari Sangathan, made statement on oath to the effect that the management had made payment to the claimant towards selection grade from 01.04.1981, granted terminal benefits on revised salary, allowed leave encashment and revised his pension. He declared that all benefits relating to revision of pension, gratuity and leave encashment have been accorded by the management to the claimant. He announced that the dispute stood satisfied.

7. As deposed by Shri Satish Kumar Sharma, authorised representative of the claimant, dispute between the claimant and the management has been satisfied, since all dues towards revision of pension, gratuity and leave encashment have been granted to the claimant. In view of these facts, it is announced that the dispute referred above for adjudication stood subsided. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated 18.04.2013 Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मई, 2013

का 1134 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी पी डब्ल्यू डी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 74/2006) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22.5.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-42012/244/2005-आईआर(सीएम- II)]
बी एम पटनायक, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd May, 2013

S.O. 1134.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 74/2006) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management CPWD, and their workmen, received by the Central Government on 22.05.2013.

[No. L-42012/244/2005-IR (CM-II)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, KARKARDOOMA
COURTS COMPLEX, DELHI.**

I.D. No. 74/2006

The General Secretary,
All India CPWD (MRM)
Karamchari Sangathan,

4823, Balbir Nagar Extention,
Gali No. 13, Shahadara,
Delhi-110032.

.....Workman

Versus

The Superintending Engineer (Elect),
Coord. Circle, CPWD,
East Block, R.K. Puram,
New Delhi.

....Management

AWARD

Arbitration Award for re-categorization and reclassification of workmen in Central Public Works Department (in short the management) was passed in the year 1988. It was implemented with effect from 01.01.1973 (notionally) and financial benefits were accorded with effect from 01.04.1981. On implementation of the Arbitration Award, post of Assistant Mechanic was merged with mechanic and they were entitled for grant of selection grade on completion of eight years of regular service.

2. Shri Sajai Kumar joined the management as mechanic on 27.04.1985. His services were regularized on 24.08.1993. He was not given wages of highly skilled category by the management. Aggrieved by that act of the management, he raised an industrial dispute. Since his claim was contested by the management, conciliation proceedings ended into a failure. On consideration of the failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. 2, New Delhi, vide order No. L/42012/244/2005-IR(CM-II), New Delhi dated 24.08.2006 with following terms:

"Whether the demand of the union for regularization of Shri Sajai Kumar, Mechanic, as well as placing him in highly skilled category with effect from 27.04.1985 is legal and justified? If yes, to what relief is the workman entitled to?

3. Claim statement was filed by Shri Sajai Kumar, wherein he pleaded that on implementation of Arbitration Award, he was to be re-classified as highly skilled artisan and placed in scale of pay of Rs. 330-560 with effect from 24.08.1993, the date of his regularization. On completion of eight years of regular service, the management, failed to grant him pay in the scales of Rs. 1200-2040.

4. Management demurred his claim projecting that vide its order dated 25.09.1998 in CWP No. 87/97 and 106/97, High Court of Delhi announced that after merger of various categories in terms of Arbitration Award, if a workman is to be upgraded to the next higher category in that stream, it would be an element of promotion and the workman had to undergo trade test, if so prescribed. It has been disputed that Shri Sajai Kumar was as Mechanic which comes under highly skilled category. It has been claimed that post of mechanic comes under skilled category.

Shri Sajai Kumar was not entitled for automatic upgradation without qualifying the trade test. He never qualified trade test, hence was not entitled to receive wages in scale of Rs. 330-560 and Rs. 1200-2040 with effect from 01.01.1986. Management projects that the claim, being devoid of merits, is liable to be dismissed.

5. Vide notification No. A-11016/3/2009-CLS-II, New Delhi dated 03.04.2013, additional charge of the post of the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, was assigned to the undersigned by the appropriate Government and thus, this case reached this Tribunal for adjudication.

6. During the course of adjudication, Shri Satish Kumar Sharma, General Secretary of CPWD (MRM) Karamchari Sangathan, made statement on oath to the effect that the management had reckoned period of service of the claimant from 04.03.1985 to 23.08.1993 for the purpose of gratuity and pensionary benefits. He announced that in view of recognition of his services for the period referred above, the dispute stands satisfied.

7. As deposed by Shri Satish Kumar Sharma, authorised representative of the claimant, dispute between the claimant and the management has been satisfied since the management had reckoned period of service of the claimant from 4.3.1985 to 23.8.1993 for the purpose of gratuity and pensionary benefits. In view of these facts, it is announced that the dispute referred above for adjudication stood subsided. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated 18.04.2013 Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मई 2013

कम 1135 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी पी डब्ल्यू डी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/2006) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22.5.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-42012/245/2005-आईआर(सीएम- II)]

बी एम पटनायक, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd May, 2013

S.O. 1135.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 73/2006) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Public Works Department, CPWD, and their workmen, received by the Central Government on 22.05.2013.

[No. L-42012/245/2005-IR (CM-II)]

B. M. PATNAIK, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE DR. R.K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
NO. 1, KARKARDOOMA COURTS COMPLEX,
DELHI**

I.D. No. 73/2006

The General Secretary,
All India CPWD (MRM)
Karamchari Sangathan,
4823, Balbir Nagar Extension,
Gali No. 13, Shahadara,
Delhi-110032.

.....Workman

Versus

The Executive Engineer (E),
Electrical Division-11, CPWD,
IARI, Pusa,
New Delhi-110012.

....Management

AWARD

A Khalasi joined as muster roll employee with Central Public Works Department (in short the management) on 03.07.1987. He was continuously engaged by the management for more than 240 days in every calendar year. His services were regularized on 16.10.2003. He left aggrieved by the said act of the management, since he claimed regularization of his services from the very date he joined on muster roll. His demand in that regard was not conceded to. He approached the all India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan (in short the Sangathan) for redressal of his grievances. The Sangathan espoused his cause and raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. Since claim was contested, conciliation proceedings ended into a failure. On consideration of failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi for adjudication *vide* order No. L-42012/245/2005-IR(CM-II), New Delhi dated 24.08.2006, with following terms:

"Whether demand of the union for regularization of services of Shri Mohan Lal, Khalasi with effect from 03.07.1987 is legal and justified? If yes, to what relief the workman is entitled?"

2. Claim statement was filed by the Khalasi, namely, Shri Mohan Lal, pleading therein that he was engaged by the management on muster roll since 03.07.1987. He rendered continuous service for more than 240 days in every calendar year. The Apex Court in *Surender Singh* (2007 (115) FLR 1003) had commanded the management to regularize services of all daily rated employees from the date of their initial appointment. Though he rendered continuous service of more than 240 days, but his services were not regularized from initial date of his engagement. The management regularized his services with effect from 16.10.2003, which

act is illegal. He claims regularization of his services with effect from 03.07.1987 with all consequential benefits.

3. Claim was demurred by the management pleading that the claimant approached the adjudicatory machinery under the provisions of Industrial Disputes Act 1947 (in short the Act) without exhausting all available opportunities. His claim, being premature is liable to be dismissed. The management projects that 8982 posts were created by Government of India in September 1992 for regularization of all eligible workman who were engaged prior to imposition of ban, *i.e.* 19.11.1985. All workers, who were eligible, were regularized from prospective date(s) and not from the date of their initial engagement. Case of the claimant is not covered by precedent in Surender Singh case (*supra*). When vacancy was available, his services were regularized. Claim projected, is devoid of merits, hence needs dismissal, pleads the management.

4. Vide notification No. A-11016/3/2009-CLS-II, New Delhi dated 03.04.2013, additional charge of the post of the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, was assigned to the undersigned by the appropriate Government and thus, this case reached this Tribunal for adjudication.

5. During the course of adjudication, Shri Satish Kumar Sharma, General Secretary of the Sangathan and authorized representative of the claimant made a statement on oath to the effect that the management had reckoned period of service of the claimant from 03.07.1987 to 30.11.1993 for the purpose of gratuity and pensionary benefits. He announced that in view of recognition of his services for the period above, claimant feels satisfied and does not want to agitate his grievance. According to him, the dispute stood resolved.

6. As deposed by Shri Satish Kumar Sharma, authorised representative of the claimant, dispute between the management and the claimant has been satisfied, since management had reckoned period of his service from 03.07.1987 to 30.11.1993 for the purpose of gratuity and pensionary benefit. The claimant feels satisfied and does not want adjudication of the dispute any further. Thus, it is evident that the dispute stood satisfied. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

DATED 18.04.2013 Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

कम 1136 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध 1 में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/1993) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 06.05.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/86/1992-आईआर(सी- I)]

एम के सिंह, अनुष्ठाण अधिकारी

New Delhi, the 23rd May, 2013

S.O. 1136.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award Ref. No. 73/1993 of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 06.05.2013.

[No. L-20012/86/1992-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) DHANBAD

Lok Adalat

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D. ACT, 1947.

Ref. No. 73 of 1993

Employers in relation to the management of Kapasara Area of M/s E.C.L.

and

Their workmen

Present: Shri Ranjan Kumar Saran,
Presiding Officer

Appearances:

For the Employers : None

For the workman : None

State : Jharkhand

Industry: Coal

Dated: 19.04.2013

AWARD

By Order No. L-20012/86/92-IR-(C-I), dt. 22.02.1993, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for regularization of S/Shri Dasu Roy and 6 ors. as per annexure for regularization as water carrier in Kapasara Colliery of M/s E.C.L. is justified? If yes, to what relief the workman are entitled to?"

ANNEXURE

1. Dashu Roy 2. Kamal Roy 3. Guhi Ram Roy 4. Ramasish Yadav 5. Jaudin Yadav 6. Kali ch. Pasndit 7. Prabhu Roy.

After receipt of the reference, both parties are noticed. They submitted Written statement and rejoinder. The case fixed for evidence. Ld. Counsel of the workman submitted

that the workman is not interested to contest the case. It is felt that there is not dispute between the parties. Hence a "No Dispute" award is passed.

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

कम 1137 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 30/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29.04.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/13/2009-आईआर(सीएम-1)]
एम के सिंह, अनुष्ठा अधिकारी

New Delhi, the 23rd May, 2013

S.O. 1137.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/2009) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 29.04.2013.

[No. L-20012/13/2009-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) DHANBAD

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D. ACT, 1947.

Ref. No. 30 of 2009

Employers in relation to the management of Bera Colliery of M/s B.C.C.L.

and

Their workmen

Present: Shri Ranjan Kumar Saran,

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers : Shri D.K. Verma, Advocate

For the workman : Shri D. Mukherjee, Rep.

State : Jharkhand

Industry: Coal.

Dated: 03.04.2013

AWARD

By Order No. L-20012/13/2009-IR-(CM-I), dated 15.05.2009, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bera Colliery of M/s B.C.C.L. in not correcting the date of Birth of Shri Khublal Mahato, Driver as 01.02.1958 instead of 11.07.1948 is justified? To what relief is the workman concerned entitled?"

2. The case is received from the Ministry of Labour on 21.05.2009. Both parties are noticed. The Union files their written statement on 06.07.2009. After that rejoinder and document received. The claim of the workman is that his date of birth is 1958, but the management holding the date of birth of the workman is 1948, Superannuated him in the year 2008, Hence the reference.

3. The case of the workman is, he was working in colliery from the year 1973, subsequently management stopped their engagement and after challenge, management engaged the workman in duty in the year 1982. From the side of the workman his identity card has been filed. His date of birth shown therein as 11.7.1948 and his date of engagement shown as March, 75 as well as 3.3.1982.

4. From the record, it appears that the workman called for his service of 1973 particulars from the management alongwith copy of form "B" register from which the correct date of birth would have been revealed.

5. It is submitted by the management that, the form "B" register of 1982 and from I.D. Card (W-1) the date of birth of the workman is 1948. The MW-1 unable to say regarding the old record. Though it has been suggested that the date of birth of the workman from the form "B" register was tempered, on close scrutiny, no such tampering pointed out.

6. Another factor is, if the date of birth of the workman will be taken as 1958 as claimed by the workman, at the time of his engagement in the year 1973 he would be 15 years old. A company cannot engage a minor in his organisation as claimed. More over from the side of workman, not a scrap of paper has been filed to prove the workman's date of birth is 1958 instead of 1948. This being the situation the date of birth mentioned in the both form "B" register and identity card (W-1) is same, it is accepted and the workman has been rightly superannuated in time.

7. Considering the facts and circumstances, I hold that the action of the management of Bera Colliery of M/s B.C.C.L. is not correction the date of birth of Shri Khublal Mahato, Driver as 01.02.1958 instead of 11.07.1948 is justified. And the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my Award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

कम 1138 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 16/2009) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 05/04/2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/09/2009-आईआर (सीएम- I)]
एम के सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 23rd May, 2013

S.O. 1138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government 05/04/2013.

[No. L-20012/09/2009-IR(CM-I)]
M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL****(NO.1), DHANBAD**IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A)
OF I.D. ACT, 1947**Ref. No. 16 of 2009**Employers in relation to the management of Angarpathra
Colliery of M/s. B. C. C. L.

and

Their workmen

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers : None

For the Workman : Sri Sachidanand Singh, Rep.

State: Jharkhand.

Industry: Coal.

Dated. 22-03-2013

AWARD

By Order No.L-20012/09/2009-IR (CM-I), dated 30.03.2009, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following

disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Angarpathra Colliery of M/s. BCCL in not Providing dependent employment to Sri Bajrang Bhuia S/o Late Ram Chandra Bhuia. Fitter Helper, under the provisions of NCWA is justified and legal? (ii) To what relief is the son of Late Ram Chandra Bhuia entitled?"

2. The case is received from the Ministry of Labour on 13.04.2009. Both parties are noticed. The Union files their written statement on 19.05.2009. After that rejoinder and document received. The short question involved in the reference, whether the dependent of the workman is entitled to be re-employed in place of the workman or not. The claim of the workman's son is that his father late Ram Chandra Bhuia died on 30.06.1995.

3. As per the certificate of BCCL Medical record and Ram Chandra Bhuia has been given notice to retire from his job on 01.07.1995 i.e. one day after his death. Therefore the workman died while on service and as such as per the Rules of the BCCL management his dependent Bajrang Bhuia is to be employed on compassionate ground. In this case BCCL has also not contested the claim of the workman for which the management has not adduced any evidence, this proves that the management is not contesting the case.

4. As per Management's written statement, the death certificate of the workman issued by the then medical officer of Angarpathra colliery of M/s. BCCL. As per the death certificate, the workman expired on 30.06.95 at 6.00 AM. Therefore the 30.06.95 was the last working day of deceased workman. This shows that the workman is in service on 30.06.95. But the workman was to retire on 01.07.1995, as per managements record filed by the workman.

4. Since the workman died during his service period, his son Bajrang is entitled to get a job on compassionate ground as per settled rule of BCCL.

5. Considering the facts and circumstance, I hold the action of the management of Angarpathra colliery of M/s. BCCL in not providing dependent employment to Shri Bajrang Bhuia S/o Late Ram Chandra Bhuia under the provision of NCWA is not justified and legal, the reference answered in favour of the workman and his son Sri Bajrang Bhuia is entitled to get job on compassionate ground.

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

कम 1139 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं० 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 58/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 06.05.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/653/1997-आईआर (सी- I)]

एम के सिंह, अनुष्ठा अधिकारी

New Delhi, the 23rd May, 2013

S.O. 1139.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government 06.05.2013.

[No. L-20012/653/1997-IR(C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

(No. 1), DHANBAD

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A)
OF I.D. ACT 1947.

Ref. No. 58 of 1998

Employers in relation to the management of Amlo Project
of M/s C.C.L.

and

Their workmen

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers. : Sri D.K. Verma, Advocate

For the Workman. : Sri K.N. Singh, Advocate

State : Jharkhand.

Industry: Coal.

Dated. 06.04.2013

AWARD

By Order No.L-20012/653/1997 -IR -(C-I), dt. 14.08.1998, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Amlo Project, CCL in Superannuating Sri Ganesh Turi, T.R. worker by not Correcting his date of Birth as per

form "B" Register, C.M.P.F records etc. is legal & justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is received from the Ministry of Labour on 01.09.1998. After notice both parties are appeared. The Workman/Union files their written statement on 30.06.1999. The short point is that the Date of Birth of the workman as mentioned in Form "B" register as 09.06.1935 or the Date of Birth mentioned in Extract of CMPF Register maintained from 07.11.1973 as 07.06.1948 is correct.

3. In this case on the basis of the Form "B" Date of Birth is 09.06.1935 and the workman has been superannuated. But on close scrutiny of the CMPF register extract and letter to Deputy Personnel Manager Amol Project from Asstt. Provident Fund Commissioner the Date of Birth of workman as 07.06.1948 which is a document sent at the earliest point of time. The CMPF Register has been maintained by the Provident Deptt. from 07.11.1973, is much more authentic. But the workman being illiterate has not stated anything regarding the CMPF register. No suggestion was given to workman that CMPF register is tampered.

4. The form "B" register filed by the management does not bear seal of the company, no date is mentioned there. The workman was illiterate, taking of his L.T.I there not within his knowledge. The management if any doubt could has referred him for medical board. Since that has not been done.

5. The Date of Birth in the CMPF Register 07.06.1948 is accepted. His superannuation has been done illegally much before.

6. Considering the facts and circumstances, the action of the management of Amlo Project, C.C.L in superannuating Sri Ganesh Turi, T.R worker by not correcting his Date of Birth as per C.M.P.F records is illegal & not justified, Therefore the workman's service continuity be maintained accepting his Date of Birth 07.06.1948. If he is superannuated in the meantime the management to clear up his dues forthwith preferably within 3 months.

This is my award.

R.K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

कम 1140 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स शुक्रिया ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं० 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 66/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09.05.2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-11012/74/2007-आईआर (सीएम- I)]

एम के सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 66/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Shukriya Travels Pvt. Ltd. and their workmen, received by the Central Government 09.05.2013.

[No. L-11012/74/2007-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE DR. R.K. YADAV PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT No. 1, KARKARDOOMA
COURT COMPLEX, DELHI**

I.D. No. 66/2007

Shri Jammal Ahmed
S/o Late Sh. Fazal Ahmed,
V-405, Gali No. 26,
Vijaya Park, Maujpur, Delhi.

...Workman

Versus

The Managing Director,
M/s. Shukriya Travels Pvt. Ltd.,
M-107, IInd Floor, Punj House,
Connaught Place,
New Delhi-110001.

...Management

AWARD

A senior counter staff was employed by M/s. Shukriya Travels Pvt. Ltd. (in short the management) on 01.10.2002 on a basic salary of Rs. 5000.00, besides other allowances. While being in service of his employer, the senior counter staff started his business also. When the senior counter staff developed his business, he stopped attending to his duties. Subsequently, he raised an industrial dispute claiming that his services were dispensed with by his employer. His claim was contested by the employer and a such conciliation proceedings ended into failure. On consideration of failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi *vide* order No.L-11012/74/2007-IR(CM-I) New Delhi, dated 16.11.2007 with following terms:—

"Whether the action of the management of Shukriya Travels Pvt. Ltd. New Delhi in discharging the services of Shri Jamal Ahmed, senior counter staff with effect from 11.07.2006 is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled to?"

2. Claim statement was filed by the senior counter

staff, namely, Shri Jamal Ahmed pleading therein that he was employed by the management with effect from 01.10.2002. His basic salary was Rs.5000.00 per month, besides other benefits. However, the management paid him Rs.4000.00 per month as basic salary, besides other allowances. When he questioned the management in that regard, he was told that the balance amount was deposited in his provident fund account every month. After about two years of his service, his salary was revised to the tune of Rs.10,000.00 per month. However, management regularly deducted Rs. 4000.00 per month from his salary, projecting that it was being deposited in his provident fund account. When he requested to make payment of balance amount of his salary, management terminated his services in an illegal manner on 11.07.2006. He served notice of demand on 15.07.2006, but to no avail. He claims reinstatement in service with continuity and full back wages, besides recovery of arrears of his salary.

3. Claim was contested by the management pleading therein that the claimant was employed as part-time employee by the management. Being a part-time employee, there was no occasion for the management to pay him basic salary of Rs.5000.00 per month, besides other allowances. He was not covered under the provisions of Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948. There was no occasion to revise his salary to Rs. 10,000.00 per month. He started working with another firm, namely M/s. AI-Falgh Associates, Bombay. He was also doing his independent business. When his business was established, he stopped attending to the duties of the management. Subsequently, false demand was raised by him. It has been projected that the claim put forth by the claimant is devoid of merits, hence it may be dismissed.

4. Arguments on maintainability of the claim were heard. Shri Himat Akhtar, authorised representative, advanced arguments on behalf of the claimant. Shri S.S. Saifi, authorised representative, raised submissions on behalf of the management. I have given my careful considerations to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues involved in the controversy are as follows:—

5. Before proceedings with the matter, it is pointed out that *vide* notification No.A-11016/3/2009-CLS-II, New Delhi dated 03.04.2013, additional charge of Central Government Industrial Tribunal No.II, New Delhi, was assigned to the undersigned by the appropriate Government and thus case reached this Tribunal for adjudication.

6. Clause (a) of section 2 of the Act defines appropriate Government. It would be expedient to know the definition of phrase 'appropriate Government'. Consequently, definition of the phrase is extracted thus:

"2(a) "appropriate Government" means—

(i) in relation to any industrial dispute concerning

any industry carried on by or under the authority of the Central Government or by a railway company or concerning any such controlled industry as may be specified in this behalf by the Central Government or in relation to an industrial dispute concerning a Dock Labour Board established under section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), or the Industrial Finance Corporation of India Limited formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Employees' State Insurance Corporation established under section 3 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), or the Board of Trustees and the State Board of Trustees section 5A and section 5B, respectively, of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), or the Life Insurance Corporation of India established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), or the Oil and Natural Gas Corporation Limited registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under section 3 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), or the Central Warehousing Corporation established under section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), or the Unit Trust of India established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), or the Food Corporation of India established under section 3, or a Board of Management established for two or more contiguous States under section 16, of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), or the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), or a Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), or the Export Credit and Guarantee Corporation Limited or the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, the National Housing Bank established under section 3 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) or the Banking Service Commission Act 1975 or an air transport service, or a banking or an insurance company, a mine, an oil field, a Cantonment Board, or a major port, an company in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the Central Government, or any Corporation, not being a Corporation referred to in this clause, established by or under any law made by Parliament, or the Central public sector undertaking, subsidiary companies set up by the principal undertaking and autonomous bodies owned or controlled by the Central Government, the Central Government,

and

- (ii) in relation to any other industrial dispute, the State public sector undertaking, subsidiary companies set up by the principal undertaking and autonomous bodies owned or controlled by the State Government, the State Government;

Provided that in case of a dispute between a contractor and the contract labour employed through the contractor in any industrial establishment where such dispute first arose, the appropriate Government shall be the Central Government or the Stated Government, as the case may be, which has control over such industrial establishment".

7. In relation to an industrial dispute, appropriate Government can either mean the Central Government or the State Government, The Central Government has been defined under section 3(8) and the State Government under section 3(60) of the General Clauses Act, 1897. In relation to an industrial dispute concerning—

1. an industry carried on or under the authority of the Central Government, or a railway company or
2. an such controlled industry as may be specified in this behalf by the Central Government, or
3. a Dock Labour Board established under section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), or
4. the Industrial Finance Corporation of India Limited formed and registered under the companies Act, 1956, or
5. the Employees' State Insurance Corporation established under section 3 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), or
6. the Board of Trustees constituted under section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), or
7. the Central Board of Trustees and the State Boards of Trustees constituted under section 5A and section 5B, respectively, of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), or
8. the Life Insurance Corporation of India established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), or
9. the Oil and Natural Gas Corporation Limited registered under the Companies Act, 1956, or
10. the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under section 3 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee

- Corporation Act, 1961 (47 of 1961), or
11. the Central Warehousing Corporation established under section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), or
 12. the Unit Trust of India established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), or
 13. the Food Corporation of India established under section 3 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964), or
 14. a Board of Management established for two or more contiguous States under section 16 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), or
 15. the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), or
 16. a Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), or
 17. the Export Credit and Guarantee Corporation Limited, or
 18. the Industrial Reconstruction Bank of India Limited, or
 19. the National Housing Bank established under section 3 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or
 20. an air transport service, or
 21. a banking company, or
 22. an insurance company, or
 23. a mine, or
 24. an oil-field, or
 25. a Cantonment Board, or
 26. a "major port, or
 27. any company in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the Central Government, or
 28. any corporation, not being a corporation referred to in this clause, established by or under any law made by Parliament, or
 29. the Central public sector undertaking, or
 30. subsidiary companies set up by the principal undertaking and autonomous bodies owned or controlled by the Central Government, the appropriate Government would mean the Central Government".

8. In relation to any industrial dispute, other than those specified in sub-clause (i) of clause (a) of section 2 of the Act, appropriate Government would be the State Government. In other words, all industrial disputes which are outside the purview of sub-clause (i) are concern of the State Government under sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Act. Thus, the general rule is that an industrial dispute raised between employer and his employee would be referred for adjudication by the State Government except in cases falling under section 2(a)(i) of the Act. Consequently, where industrial dispute concerning on industry which does not fall within the ambit of section 2(a)(i) of the Act, appropriate Government cannot be the Central Government.

9. Shri Akhtar concedes that the present dispute is outside the purview of sub-clause (i) of clause (a) of section 2 of the Act. He candidly admits that this Tribunal has no jurisdiction to entertain the dispute, since appropriate Government for making reference of the dispute was the State Government. Shri Akhtar was right when he made admission to the effect that Central Government was not the appropriate Government for making reference of the dispute to this Tribunal for adjudication. Thus, it is crystal clear that reference of the dispute by the Central Government to this Tribunal was incompetent. In such a situation, the Tribunal cannot invoke its jurisdiction for adjudication of the dispute. Dispute referred is not competent. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated: 01.05.2013

Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

कम 1141 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या CGIT-1/46 of 2003) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 29/04/2013 को प्राप्त हुआ था।

सं एल-11012/46/1999-आईआर (सीएम- I)
एम के सिंह, अनुष्ठा अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1141.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. CGIT-I/46 of 2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Indian Airlines and their workmen, received by the Central Government on 29/04/2013.

[No. L-11012/46/1999-IR (CM-I)]
M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1**

MUMBAI

Present

JUSTICE G.S. SARRAF

Presiding Officer

Reference No. CGIT-1/46 of 2003

Parties : Employers in relation to the management of
Air India Ltd.

And

Their workmen

Appearances:

For the Mumbai Mazdoor Sangh : Mr. M.B. Anchan,
Adv.

For the Air India : Mrs. Pooja Kulkarni,
Adv.

For the Livewell Aviation
Services Pvt. Ltd. : Ms. Purav, Adv.
State : Maharashtra

Mumbai, dated the 2nd Day of April, 2013

AWARD

1. This is a reference made by the Central Government in exercise of its powers under clause (d) of sub section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act). The terms of reference given in the schedule are as follows:

1. Whether the contract between Indian Airlines Ltd. and M/s. Livewell Aviation Service, is sham and bogus and is a camouflage to deprive the workers concerned in the petition No. 2163/99 before the Mumbai High Court, of benefits available to permanent workmen of Indian Airlines Ltd.?
2. Whether the workers concerned in the petition should be declared as permanent workers of Indian Airlines Ltd.?
3. What are the wages and consequential benefits to be paid to the workmen concerned in the petition?

2. According to the statement of claim filed by Secretary, Mumbai Mazdoor Sangh (hereinafter referred to as the Union) the workmen were employed as aircraft cleaners, cabin cleaners, hanger cleaners, carpet cleaners etc. for the services of the Indian Airlines (Now Air India) through M/s. Livewell Aviation Services (hereinafter refer

to as the Contractor) for years together and for more than 240 days in a year and every year. Though the nature of work of the workmen is of perennial nature, the Air India did not make the workmen permanent deliberately and this constituted unfair labour practice. During the pendency of conciliation proceedings before Asstt. Labour Commissioner (Central), Mumbai all the workmen except 22 were discontinued from the employment by the Contractor with a view to bring pressure on the workmen not to pursue their remedy. The Contractor has done this without obtaining permission from the appropriate authority and, therefore, this amounts to illegal termination. Since the dispute was not considered fit for adjudication the Union filed a writ petition 2163 of 1999 before the Bombay High Court. Honourable High Court was pleased to allow the said writ petition and directed the Central Government to make a reference of the dispute to the Industrial Tribunal for adjudication. Accordingly the Central Government has referred this dispute to this Tribunal. According to the statement of claim the action of the Air India to employ the workmen through the Contractor by entering into sham and bogus contract is illegal and bad in law. On the one hand the Air India denied the need of the workmen and on the other hand it employed new persons in place of the workmen. The workmen worked with the Air India from 1984 to 1999 but no workman has been paid any compensation or notice pay as envisaged under Section 25-F of the Act. It has, therefore, been prayed that it be declared that discontinuance or termination of the workmen is void ab initio and it be held that the contract between the Air India and the Contractor is sham and bogus and is a camouflage and the Air India be directed to make the workmen permanent.

3. According to the written statement filed by the Air India the Contractor is a company rendering various services related to the aviation industry specializing in highly technical expertise and experience in aircraft cleaning and hygiene under the direct supervision of its highly qualified management team. The work of the aircraft cleaning is done by using sophisticated and most modern and internationally approved aviation materials. The job of interior and exterior cleaning of aircraft is done by trained manpower of the Contractor with specialized equipments for various domestic and international airlines. The Contractor has entered into contracts with other international and domestic airlines also for the said purpose. Regular and permanent work force is appointed by the Contractor and the workmen are imparted with special training. They are liable to be transferred from one area of activity to another and from one establishment to another where similar activities are carried out. Consequent to the Central Government adopting the open sky policy several private airlines entered the domestic aviation industry giving rise to tough competition. Since the Air India did not have the resources it had no option but to take a policy decision and in furtherance thereof entered

into a contract with the Contractor for up keep and maintenance of aircrafts. The contract was entered into in 1996 and it has been renewed after regular intervals. The Contractor is holding valid licenses from the appropriate authority for the contracts awarded to it from time to time. The workmen are not employees of Air India. The workmen have not been employed by Air India and they have been appointed by the Contractor. The Union has no *locus standi* to represent the workmen. The contract between the Air India and the Contractor is genuine and such contracts are not prohibited by law. The Air India has prayed that the reference be rejected.

4. The Union has filed rejoinder wherein it has reiterated its stand.

5. According to the written statement filed by the Contractor it is engaged in business of providing various types of aviation services to the airline companies such as Air India, Jet Airways, Alliance Airways etc. It engages its own workmen, staff, supervisors, officers, managers etc. for the said services. There is no division of the workmen that one particular group of workmen will work for a particular airlines as such all the workmen work for all the client airline companies and, therefore, the demand of the Union against the Air India is false and frivolous. It appoints the workmen and terminates them without interference by its client airlines companies. In fact its workmen are represented by Bhartiya Kamgar Sena and not by the Union. Out of the 109 workmen only 19 workmen are in its employment and these workmen work for all the airline companies. The wages and the benefits are paid to the workmen as agreed by it and Bhartiya Kamgar Sena. The wages are fair and proper and commensurate with its capacity to pay the same. The workmen have been employed by it and it has not terminated the services of any workman. According to the written statement the prayer of the Union is wholly misconceived, unjustified and untenable and deserves to be rejected in toto.

6. The Union has filed affidavit of Suresh Yadav Baile and he has been cross examined by learned counsels for the Air India and the Contractor. The Air India has filed affidavit of R.A. Kamath and he has been cross examined by learned counsel for the Union. The contractor has filed affidavit of Sairaj Khatri but his statement cannot be read in evidence as his cross examination was incomplete and he could not be produced by the Contractor for completing his cross examination.

7. Heard Mr. Anchan learned counsel for the Union. Mrs. Pooja Kulkarni learned counsel for the Air India and Ms. Purav learned counsel for the Contractor.

8. Let me state at the outset that there is absolutely no evidence on the record to prove that the contract between the Air India and the Contractor is sham and bogus

and is a comouflage to deprive the workmen all benefits available to permanent workmen of the Air India.

9. The sole witness of the Union Suresh Yadav Baile has stated in his cross examination.

No appointment letter was issued by the Indian Airlines. The workmen were kept by the Contractor.

He has further stated in his cross examination:

I know that Livewell Services provides services to other Airlines by appointing labourers/workmen. Livewell Aviation Services is expert for providing cabin cleaning and aircraft cleaning. Our duties are assigned by Livewell. The timings of the shift for working are decided by Livewell. The terms and conditions are decided by Livewell. The attendance for duty is recorded by Livewell. The leave is granted by Livewell. We work under the supervision of supervisor appointed by Livewell.

He has also stated in his cross-examination

I was given uniform by Livewell with its logo. I was issued attendance card by Livewell with its logo. The supervisor of Livewell used to remain present in the flight at the time of cleaning work.

10. I fail to understand how the workmen who are admittedly the employees of the Contractor can be absorbed and made permanent by the Air India.

11. The workmen have been appointed by the Contractor, their duties are assigned and the terms and conditions of services are decided by the Contractor, their attendance is recorded and leave is granted by the Contractor and they work under the supervision of the supervisor appointed by the Contractor. It is thus clear that the workmen are the employees of the Contractor and, therefore, they have no right to be declared as permanent workmen of the Air India.

12. In view of the above discussion Air India is not liable to pay wages and consequential benefits to the workmen.

The workmen are not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

JUSTICE G. S. SARRAF, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

का आ 112 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय ने 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 141/2000) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 13/05/2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/506/1999-आईआर (सी- I)]

एम के सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1142.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 141/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 13/05/2013.

[No. L-20012/506/1999-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1),**

DHANBAD.

Lok-Adalat.

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2) OF
I.D. ACT, 1947

Ref. No. 141 of 2000

Employers in relation to the management of Bhowra (S)
Colliery of M/s. B.C.C.L.

And

Their workmen.

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers. :- Sri D.K. Verma, Advocate

For the workman. :- None

State: Jharkhand.

Industry:- Coal.

Dated 26.04.2013

AWARD

By Order No. L-20012/506/99IR(C-I), dt. 01/03/2000 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Bhowra South Colliery of M/s. BCCL in not regularising Sri Ramu Lal to the post of Chainman and in not paying the difference of wages is justified? If not to what relief is the workman is entitled?"

After receipt of the reference, both parties are noticed.

They submitted Written Statement and rejoinder. But in spite of red. notice, parties did not turn up nor adduce any evidence by both side. Ld. Counsel of workman submits that the Union/workman is not connected. Therefore it is felt that there is not dispute between the parties. Hence a "No Dispute" award is passed.

R.K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई 2013

का आ 1143 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 77/1993) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29/04/2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/87/1992-आईआर (सी- I)]

एम के सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1143.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 77/1993) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 29/04/2013.

[No. L-20012/87/1992-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1),**

DHANBAD.

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A)
OF I.D. ACT, 1947

Ref. No. 77 of 1993

Employers in relation to the management of Shyampur 'B'
Colliery No. XI of M/S.E.C.L.

And

Their workmen.

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding officer

Appearances:

For the Employers. :- Sri D.K. Verma, Advocate

For the workman. :- None

State :- Jharkhand.

Industry:- Coal.

And

Dated 03/04/2013

Their workmen.

AWARD

By Order No. L-20012/87/1992-IR (C-I), dated 22/02/1993, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for regularisation of Shri Bhagat Routh for regularisation as water Carrier in Shampur "B" Colliery of M/s. E.C. Ltd. is justified? If yes, to what relief the workman is entitled to?"

After receipt of the reference both parties are noticed. But none appears. After joining of this Presiding Officer both parties are again noticed by regd. post on 15.10.12. Still then none appears. It is felt that the Union lost interest in the case. Hence "No Dispute" award is passed. Communicate to the ministry.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई 2013

कम 1144 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 69/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 06/05/2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/81/2004-आईआर (सी- I)]

एम के सिंह, अनुष्ठा अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1144.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 69/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 06/05/2013.

[No.L-20012/81/2004-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No.1), DHANBAD**

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D. ACT, 1947.

Ref. No. 69 of 2004

Employees in relation to the management of Kustore Area of M/S B.C.C.L.

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding officer

Appearances:

For the Employees :—Sri U.N. Lal, Advocate

For the workman :— None

State:- Jharkhand

Industry:- Coal.

Dated. 11/04/2013

AWARD

By Order No.L-20012/81/2004-IR-(C-I), dt. 02/07/2004, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh from the management of Kustore Colliery under Kustore Area of M/S BCCL for giving monetary compensation to the dependent daughter namely Parbatia Kumari and Suma Kumari of late Kushalya Bhuini, Ex-coal Breaker for the period from July 1997 to August 2000 is proper and justified? If so, to what relief are the said dependent daughters of the deceased employee entitled?"

2. The case is received from the Ministry of Labour on 12.07.2004. After notice both parties are appeared. The Union/workman files their written statement on 15.12.2004 and thereafter rejoinder is also filed. The short question to be decided in the reference is the daughters of the deceased workman, who died during her service period entitled to monetary compensation or not as per NCWA.

3. The daughters of the dependent though claim for monetary assistance, the management, submitted that since the workman died during her service period, her dependent daughter who was unmarried, suma Kumari got employed by the BCCL management. Therefore as per the provisions of the NCWA no monetary compensation is to be paid.

4. Considering the facts and circumstances, I hold that the demand of Janta Mazdoor Sangh from the management of Kustore colliery under Kustore Area of M/s. BCCL for giving monetary compensation to the dependent daughter namely Parbatia Kumari and Suma Kumari of late Kushalya Bhuini Ex-coal Breaker for the period from July 1997 to August 2000 is not proper and justified. Therefore the claimant are not entitled to any relief what so ever in the reference.

This is my award

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 मई 2013

कम 1145 —आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं० 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 30/1995) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 05/04/2013 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-20012/119/1994-आई आर (सी- I)]

एम के सिंह, अनुष्ठाण अधिकारी

New Delhi, the 24th May, 2013

S.O. 1145.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/1995) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 05/04/2013.

[No. L-20012/119/1994-IR(C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1), DHANBAD.

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A)
OF I.D. ACT, 1947.

Ref. No. 30 of 1995

Employers in relation to the management of Bhowra Area
No. XI of M/S.B.C.C.L.

And

Their workmen.

Present: Sri Ranjan Kumar Saran,

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers. :- Sri U.N. Lall, Advocate

For the workman. :- Sri C. Prasad, Advocate

State:- Jharkhand

Industry:- Coal.

Dated. 15/03/2013

AWARD

By Order No.L-20012/119/1994-IR (C-I), dated. 29/03/1995, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause

(d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhowra Area No.XI of M/S BCCL in dismissing Smt. Archanna Samanta, Ex-Staff Nurse w.e.f. 18.8.87 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Though both sides have filed their claim statements, none appears since last several years to file any documents in support of their claim. After joining of this Presiding Officer parties are again noticed. The Notice of the workman is returned back, but learned counsel of the workman submits that the concerned workman is traceless since last several years and not connected with me as such he is not interested proceed with the case. It is felt that the parties have lost interest in the case. Hence "No Dispute" award is passed. Communicate to the Ministry.

R.K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1146 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात:

केन्द्र	निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव
नल्लरी क्षेत्र तथा इलयिरामपट्टे,	1 नल्लरी
सातुर तालुक	2 करिसलपट्टे
विरुदुनगर जिला	3 चिन्नतम्बियापुरम
	4 धर्मसनम चिन्न ओड्डयपट्टे
	5 परियम्पट्टे
	6 माडम चिन्न ओड्डयपट्टे
	7 मुल्लिसेवल
	8 सुब्रमणियमपुरम
	9 कंजम्पट्टे
	10 पोथी रेड्डयपट्टे
	11 पेयु रेड्डयपट्टे
	12 इलयिरामपट्टे
	13 संकरपाण्डियपुरम
	14 उयुपट्टे
	15 सर्वेकरपट्टे
	16 ई रामनाथपुरम
	17 ई रेड्डयपट्टे
	18 सननकुल्लम
	19 मुंशडियापुरम
	20 कंकरकौट्टे
	21 कुलानपट्टे
	22 सुंयुंय

[सं एस-38013/39/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1146.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2013 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of **Tamil-Nadu** namely:-

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of
Nalli & Elayirampannai, Sattur Taluk, Virudhunagar District	1. Nalli 2. Karisalpatti 3. Chinnathambiapuram 4. Dharmasanam Chinna Odaipatti 5. Peraiyampatti 6. Madam Chinna Odaipatti 7. Mulliseval 8. Subramaniapuram 9. Kanjampatti 10. Pothi Reddipatti 11. Pethureddipatti 12. Elayirampannai 13. Sankarapandiapuram 14. Uthupatti 15. Servaikaranpatti 16. E. Ramanathapuram 17. E.Reddiapatti 18. Sanankulam 19. Muthandiapuram 20. Kankarakottai 21. Kuganparai 22. Surangudi

[No. S-38013/39/2013-SS-I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1147 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा **01 जुलाई 2013** को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रकृत हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा- 77,78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रकृत की जा चुकी है] के उपबंध **हरियाणा** राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात:

क्रमांक	राजस्व भाग	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1	धनकोट	49	गुडगांव	गुडगांव

[सं एस-38013/40/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1147.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2013, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely:—

Sl. No	Name of Revenue Village	Had bast Number	Name of Tehsil	Name of District
1	Dhankot	49	Gurgaon	Gurgaon

[No. S-38013/40/2013-SS-I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1148 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा **01 जुलाई 2013** को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रकृत हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा- 77,78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रकृत की जा चुकी है] के उपबंध **उड़ीसा** राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात:

“जिला जाजपुर की दर्पण तहसील में (1) सुंगुडा, (2) रामचन्द्रपुर, (3) देबतासाही, (4) दर्पणगढ़ (5) बड़चणा, (6) खोसालीपुर, (7) देउलकुर के राजस्व गांव एवं जिला जाजपुर की धर्मशाला तहसील में कांटीगाडिया एवं नेउलपुर के राजस्व गांव।

[सं एस-38013/41/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1148.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2013, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Odisha namely:—

"THE AREAS COMPRISING OF THE REVENUE VILLAGES OF SUNGUDA, RAMACHANDRAPUR, DEBATASAH, DARPANGARH, BARCHANA, KHOSALIPUR, DEULKUR in the Tahasil of Darpan and KANTIGADIA & NEULPUR in the Tahasil of Dharmasala, in the District of Jaipur."

[No. S-38013/41/2013-SS-I]
NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1149 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला अनगुल की कणिहां तहसील में आलोरी, रासोल, बारडांगूआ, गदाशिला, करदेई, बलरामपुर, पथरमुण्डा, छेलिआ, दण्डसिंहा, टकुआ, तालकबेडा, रंगबेडा, कमरेई, बिजिगोल, भीमकांड, काटेणी, नकनका, कणिहाँ, काण्डसर, काईशवेरेणी, सारथीपाल, आम्बपाल, लोधाबंध, किशोरचन्द्रपुर जंगल, सुनाखणी, शिवरामपुर, रूतुभूई, जदूनाथपुर, बलंगी, हरिहरपुर, जैना तथा मसुणीहता के राजस्व गांव।

[सं एस-38013/42/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1149.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2013, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Odisha namely:—

"THE AREAS COMPRISING OF THE REVENUE VILLAGES OF ALLORI, RASOL, BARDANGUA, GADASILA, KARADEI, BALARAMPUR, PATHARMUNDA, CHELLIA, DANDASINGHA, TAKUA, TALAKABEDA, RANGABEDA, KAMAREI, BIJIGOL, BHIMKAND, KATANI, NAKANAKA, KANIHA, KANDASAR, KAUNSIBERENI, SARATHIPAL, AMBAPAL, LODHABANDHA, KISHORECHANDRAPUR JUNGLE, SUNAKHANI, SIBARAMPUR, RUTUBHUIN, JADUNATHPUR, BALANGI, HARIHARPUR, DERANGAAND MASUNIHATA. in the Tahasil of Kaniha of District. Angul."

[No. S-38013/42/2013-SS-I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1150 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई 2013 को उस

तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम क

अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

“आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले के गन्नावरम् मण्डल के सुरमपल्लि तथा अगिरीपल्लि मण्डल के अड़वीनेकलम् के राजस्व गाँवों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।

[सं एस-38013/43/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1150.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2013, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:—

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE REVENUE VILLAGES OF SURAMPALLY OF GANNAVARAM MANDAL AND ADAVINEKKALAM OF AGIRIPALLY MANDAL OF KRISHNADISTRICT IN ANDHRA PRADESH."

[No. S-38013/43/2013-SS-I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

कम 1151 —इस मंत्रालय की दिनांक 07021981 की समसंख्यक अधिसूचना संख्या (काआ सं 92 (अ) भारत के राजपत्र सं 61, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) दिनांक 1 फरवरी 1981 पृष्ठ सं 215 पंक्ति सं 9 में प्रकाशित शब्द 'इलवाथिरुथी को 'एजुवतिरुथि पढ़ जाए।

[सं आई डी-55435/एफटीएस/2013-एसएस- I]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th June, 2013

S.O. 1151.—In this Ministry notification of even number dated 7th February, 1981 S.O. No. 92(E), published in the Gazette of India No. 61, Part-II, Section-3, Sub-Sec. (ii) dated 7th February, 1981, at page number 216, in 9th line, the words "Elavathiruthy" may be read as "EZHUVAATHIRUTHY"